

पत्रांक—7 / स्था० ०४—२९ / २०२३ सा० प्रा० ९६६। /

**बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग**

प्रेषक, गुफरान अहमद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,
महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना—१५, दिनांक २०.०६.२०२४

विषय— बिहार उच्च न्यायिक सेवा के १४० (एक सौ चालीस) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक—३६५७१ दिनांक ०७.०५.२०२४ द्वारा बिहार उच्च न्यायिक सेवा के १४० (एक सौ चालीस) अस्थायी पदों को स्थायी करने की अनुशंसा संसूचित की गयी है।

२. बिहार उच्च न्यायिक सेवा का उक्त १४० पद पूर्व में अस्थायी रूप से सृजित किया गया है, जिसके भविष्य में भी बने रहने की संभावना को देखते हुए इसे स्थायी किये जाने की अनुशंसा माननीय न्यायालय द्वारा की गयी है।

३. उक्त अनुशंसा पर सम्यक् विचारोपरांत संलग्न व्यय विवरणी में अंकित पद संवर्ग के सम्मुख वेतनमान में ₹ ४१,६३,६२,८००/- (एकतालीस करोड़ तिरसठ लाख बासठ हजार आठ सौ रुपये) मात्र के वार्षिक व्यय तथा न्यायिक सेवा संवर्गों में समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्तों के अनुमानित व्यय भार पर गैर योजना मद में स्थायी रूप से बिहार उच्च न्यायिक सेवा के १४० (एक सौ चालीस) अस्थायी पदों को स्थायी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

४. उपर्युक्त सृजित किये जाने वाले पद का व्यय—बजट शीर्ष वही होगा, जो राज्य के व्यवहार न्यायालयों के न्यायिक पदाधिकारियों का होगा एवं संबंधित जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

५. इसमें प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति एवं मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नकः—व्यय विवरणी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
 ४०८५८८
 (गुफरान अहमद)
 सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-7 / स्था०-०४-२९ / २०२३सा०प्र०..... १६६/..... / पटना-१५, दिनांक २०.०६.२४

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-36571 दिनांक 07.05.2024 के प्रसंग में/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 20.06.2024 के मद संख्या-14 के प्रसंग में/सुन्नी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी कोषागार पदाधिकारी एवं आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।